

अति महत्वपूर्ण

संख्या: ५९०३ आर/छ:-पु-५-५४२/९७

प्रेषक,

अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-५

लखनऊ: दिनांक: अप्रैल १७, १९९८

विषय: जेल कर्मियों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वरीयता के आधार पर अनिषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंस प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ३५२० आर/छ:-पु-५-५२६/९५, दिनांक १७ जनवरी, १९९७ के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कारागार विभाग के ऐसे अधिकारी जिन्होंने आत्मरक्षार्थ एक आग्नेयास्त्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्राधिकृति के आधार पर जॉच कराकर आयुध अधिनियम १९५९ एवं नियमावली १९६२ के प्राविधानों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक तत्काल निर्णय लिया जाय। इस संबंध में कृपया संबंधित जेल कर्मी की सामान्य ख्याति, को आवश्यक रूप से देखने के उपरान्त शस्त्र अधिनियम १९५९ के अनुरूप केवल पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को ही लाइसेंस निर्गत किया जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।

पुष्टांकन संख्या तथा दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि:- १- प्रमुख सचिव, कारागार, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- महानिरीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राम रत्न)
अनु सचिव।